गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 049
दि. 18.06.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

विकास भी, विरासत भी

गुजरात सरकार

अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण
काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक
और केदारनाथ धाम का कायाकल्प

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प तक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति देते हुए हमारी विरासत को वैश्विक गौरव के शिखर पर स्थापित किया है।
- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

मुख्यमंत्री के करकमलों से एनईपी-2020 पर आधारित 'स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क', और 'स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क' पुस्तक का लोकार्पण तथा 'निपुण गुजरात कार्यक्रम' का शुभारंभ

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी महोत्सव 2026 को लेकर मार्गदर्शक बैठक

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आह्वान- "शाला प्रवेशोत्सव को प्रगति का प्रवेशोत्सव बनाने के संकल्प के साथ बच्चों के 100 फीसदी शाला नामांकन से गुजरात को शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर वन बनाएं"

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा और राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की विशेष उपस्थिति

▸▸ यदि बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और सद्गुणों का विकास हो, तभी वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ गुजरात ने शाला प्रवेशोत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव दृष्टिकोणों के जरिए 100 फीसदी नामांकन के साथ बेहतर सुविधा वाले स्कूलों का लक्ष्य हासिल किया : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

गांधीनगर : राज्य में शिक्षा के सर्वांगीण विकास और प्रत्येक बालक तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर में 'शाला प्रवेशोत्सव-2026' और 'कन्या केळवणी महोत्सव-2026' कार्यक्रम को लेकर मार्गदर्शक बैठक आयोजित हुई।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा और प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की विशेष उपस्थिति में शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर आधारित 'स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क' (एससीएफ) तथा स्कूलों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए 'स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क' (एसक्यूएएएफ) पुस्तक का मुख्यमंत्री सहित महानुभावों ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक, तीन वर्षों के लिए महत्वपूर्ण 'निपुण गुजरात कार्यक्रम' का भी शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस वर्ष के शाला प्रवेशोत्सव को प्रगति का प्रवेशोत्सव बनाने के संकल्प के साथ बच्चों के 100 फीसदी शाला नामांकन से गुजरात को शिक्षा क्षेत्र में भी नंबर वन बनाने का आह्वान किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी महोत्सव के दौरान स्कूलों में जाने वाला प्रत्येक अधिकारी और पदाधिकारियों को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठक में अभिभावकों को शिक्षा के महत्व और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता के विषय में समझाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, "यदि हम बच्चों के 100 फीसदी स्कूल नामांकन के लिए क्या करना है और किस प्रकार करना है, इस निश्चित लक्ष्य और विजन के साथ आगे बढ़ेंगे और अभिभावकों को समझाएंगे, तो एक भी बच्चा शाला प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 23 वर्ष पहले शुरू किया गया यह शिक्षा सेवा यज्ञ अविरत रूप से 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही बारीकी से छोटी-छोटी बातों की चिंता करके हमें यह दिशा दी है कि किस प्रकार अपार संभावनाओं से हर दिन और बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने राज्य में ड्रॉपआउट रेट घटकर 1 फीसदी तक पहुंचने की सराहना की और कहा कि यह 100 फीसदी नामांकन पर हमारे फोकस का नतीजा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह भी कहा कि शाला प्रवेशोत्सव के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि हम बच्चों के पठन, लेखन और गणना पर ध्यान केंद्रित करके गुणोत्सव को भी सफल बनाएं और सुनिश्चित करें कि 100 फीसदी विद्यार्थी पास हों। मुख्यमंत्री ने विकास के अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा में भी गुजरात को नंबर वन स्थान पर पहुंचाने के लिए इस शिक्षा सेवा यज्ञ में सभी के साझा प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि बच्चों के लिए केवल किताबी ज्ञान या शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षकों को चाहिए कि वे उनके दैनिक जीवन की आदतों, संस्कारों और कौशल को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दें। बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और सद्गुणों जैसी आदतें विकसित होंगी, तभी वे भविष्य में एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बन सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे शाला प्रवेशोत्सव के इस तीन दिवसीय कार्यक्रम को केवल एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में न लेते हुए, तन-मन से जुड़कर बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल में आकर स्वच्छता बनाए रखें, भोजन से पहले हाथ धोएं और सुबह की दैनिक आदतों को सुधारें, इस दिशा में शिक्षकों को अभिभावकों को साथ रखकर सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

उन्होंने इससे पूर्व चालू सत्र के दौरान स्कूल छोड़ चुके लगभग साढ़े छह लाख बच्चों को ढूंढ़कर स्कूल तक पहुंचाने का उत्तम कार्य करने के लिए शिक्षा विभाग और पूरे प्रशासनिक तंत्र की टीम को बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी दिनों में समाज के सहयोग और राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य में ड्रॉपआउट अनुपात शून्य तक पहुंच जाएगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने शिक्षा क्षेत्र में गुजरात की गौरवशाली उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में गुजरात ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं, राज्य के 15 स्कूलों ने भी इस प्रतिष्ठित रेटिंग में अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में देश के श्रेष्ठ 10 जिलों में राजकोट जिले को सातवां स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री ने इन उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समूचे शिक्षा विभाग, शिक्षकों, विद्यार्थियों और गुजरात की जनता को बधाई दी।

शिक्षा मंत्री डॉ. वाजा ने 'स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क' और 'स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क' पुस्तकों के साथ ही निपुण गुजरात अभियान के त्रिवेणी शुभारंभ को शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात ने शाला प्रवेशोत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव दृष्टिकोणों से 100 फीसदी नामांकन और सुविधा युक्त स्कूलों का लक्ष्य हासिल किया है। अब, राज्य सरकार का मुख्य ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने आगे कहा कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना के जरिए सरकारी और निजी सहित सभी स्कूलों के लिए एक समान गुणवत्ता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जीसीआरटी द्वारा तैयार किए गए निर्धारत मापदंडों के आधार पर स्कूलों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करके उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति-2020 और निपुण गुजरात अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सृजनात्मकता, नवाचार, शोधवृत्ति और 'लर्निंग बाय डूइंग' के नजरिए को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव गुजरात के लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन और शिक्षा उत्सव बन गया है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी गांव तक जाकर बच्चों के नामांकन और स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने इस वर्ष विशेषकर स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावकों और समाज को शिक्षा प्रक्रिया में और भी सक्रिय भागीदार बनाने पर बल दिया।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने कहा कि हर बच्चा स्कूल में प्रवेश प्राप्त करके शिक्षित बने, इस बात की चिंता करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 से गुजरात में पहली बार शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की थी, जो शिक्षा यज्ञ आज भी अविरत जारी है। इस शिक्षा यज्ञ से आज गुजरात में शिक्षा की स्थिति और गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आया है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में भी पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का हर बच्चा स्कूल में प्रवेश लेगा और नियमित रूप से स्कूल जाएगा, तभी शिक्षा के प्रतिशत में और वृद्धि होगी। इसके अलावा, स्कूल छोड़कर गए बच्चों के स्कूल वापस आने पर ही ड्रॉपआउट अनुपात घटकर शून्य होगा। अधिक से अधिक बच्चे शाला में प्रवेश लें, इसके लिए हमें शाला प्रवेशोत्सव के दौरान अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों, अग्रणियों और नागरिकों से मिलकर उन्हें समझाना होगा। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना जरूरी है, ये बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि गुजरात जिस प्रकार हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, उसे हम फिर से अपने संयुक्त प्रयासों से शिक्षा क्षेत्र में भी अग्रणी बनाएं।

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मिलिंद तोरवणे ने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव-2026 केवल नए विद्यार्थियों के प्रवेश का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राज्य के प्रत्येक बालक को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने का एक व्यापक जनआंदोलन है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुई यह यात्रा आज 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस वर्ष बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों की डेटा-आधारित मैपिंग के जरिए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके अलावा, विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने के जोखिम वाले विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए राज्य व्यापी अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य डेटाबेस के समन्वय से हर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर कमिश्नर ऑफ स्कूल्स और जीसीईआरटी के निदेशक श्री आनंद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के बुनियादी स्तंभ के रूप में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक और ठोस कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू 21वीं सदी की पहली 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सक्रिय प्रयास करके आज शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण प्रकल्पों को लॉन्च किया है। उनके द्वारा एससीएफ, एसक्यूएएएफ और निपुण गुजरात अभियान की विशेषताएं दिखाने वाली छोटी और जानकारीपूर्ण शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री प्रकाश त्रिवेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री सहित महानुभावों के करकमलों से वर्ष 2026-27 के बजट में स्वीकृत 298 माध्यमिक स्कूलों में से 5 स्कूलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकार पत्र सौंपे गए।

इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक संघों के पदाधिकारी और शिक्षकों सहित कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी और तहसील एवं जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 'विकसित गुजरात 2047' विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम

▸▸ हुडको राज्य की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का दीर्घकालिक वित्तपोषण करेगा

▸▸ मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति में राज्य सरकार और हुडको के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए

▸▸ विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए आईआईएम-अहमदाबाद और राज्य सरकार के बीच एमओयू

▸▸ एक्सप्रेस-वे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, धोलेरा में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 एवं 3 जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाएं शामिल

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 में विकसित गुजरात 2047 से अग्रणी रहने के विजन को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में साकार करने की दिशा में गुजरात ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।'

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की विशेष उपस्थिति में मंगलवार को गुजरात सरकार और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से राज्य की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई और राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल भी मौजूद रहे।

राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा क्रियान्वित होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंडिंग को लेकर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और हुडको के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के नतीजे के रूप में हुडको दीर्घकाल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड देगा। इस फंड में गुजरात मेट्रो रेल के फेज-2 और फेज-3, एक्सप्रेस-वे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और धोलेरा में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी विकासोन्मुखी परियोजनाओं के कार्य शामिल होंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने एक दूसरा एमओयू भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के साथ भी किया है। इस एमओयू के अनुसार, आईआईएम-अहमदाबाद विकसित गुजरात 2047 की विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ ही इंपैक्ट असेसमेंट करेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आशा व्यक्त की कि इस ऐतिहासिक भागीदारी से राज्य के बुनियादी ढांचा विकास, शहरी पुनर्निर्माण और सर्वांगीण आर्थिक विकास को और गति मिलेगी।

राज्य सरकार और हुडको के बीच हुए इस एमओयू पर हुडको की ओर से चेयरमैन सह प्रबंधन निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ तथा राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग में आर्थिक मामलों के सचिव श्री संदीप कुमार ने हस्ताक्षर किए और एमओयू का आदान-प्रदान किया। आईआईएम-अहमदाबाद के साथ हुए एमओयू पर आईआईएम-अहमदाबाद के पब्लिक सिस्टम ग्रुप चेयरपर्सन प्रो. संदीप चक्रवर्ती ने हस्ताक्षर किए।

इस समारोह में मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस.एस. राठौर, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संपादकीय

'चिट्टा' को चुनौती

हाल के दिनों में पंजाब के बाद, हिमाचल के लिए भी नशीले पदार्थों का तेजी से बढ़ता दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है। नशे के बढ़ते सेवन की जो समस्या कभी सीमावर्ती राज्यों व सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी, अब दुर्भाग्य से वह इस पहाड़ी राज्य के गांवों तक पहुंच गई है। जिससे कई परिवारों का अस्तित्व, लोगों की आजीविका और युवा पीढ़ी का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे हालात में राज्य सरकार का वह फैसला एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिसमें नशीले पदार्थों से मुक्ति के अभियान 'चिट्टा-मुक्त गांव' में पंचायतों को शामिल करने का रणनीतिक निर्णय लिया गया है। सालों तक इस संकट को कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न माना जाता रहा है। नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिये सप्लायरों व नशे की आदत का शिकार लोगों की गिरफ्तारी, नशीले पदार्थों की बरामदगी और पुलिस की कार्रवाई को प्राथमिकता बना लिया गया था। निस्संदेह, कानून के अनुपालन के बिना इस संकट का समाधान संभव भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इन प्रयासों से सफलता कम ही मिली। नशीले पदार्थ बेचने वालों की गिरफ्तारी के बाद सप्लाई चेन तेजी से बदल जाती है। नशे के कारोबारी स्थानीय तंत्र की कमजोरी का लाभ उठाते और नये लोग नशे की लत की चपेट में आ जाते थे। इस संकट के बने रहने ने संकेत दिए कि यह समस्या सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि इसे एक सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संकट के रूप में भी देखा जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से किसी ग्रामीण समाज में पंचायतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायतें ग्रामीण परिवेश में स्थानीय हालात को बेहतर ढंग से समझती हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय समुदायों का विश्वास भी हासिल होता है। वे गांव के लोगों के व्यवहार संबंधी बदलावों को आसानी से से पहचान सकती हैं। ऐसे बदलाव जिन्हें दूर बैठे प्रशासन व पुलिस के अधिकारी नहीं समझ सकते।

इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि यदि पंचायतों को प्रभावी अधिकार और संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो वे जागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। साथ ही ग्रामीण परिवारों को समय रहते मदद लेने को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, वे इस जागरूकता अभियान का दायरा बढ़ाने और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सार्थक तालमेल स्थापित कर सकती हैं। साथ ही बिना किसी भेदभाव के, संवेदनशील ढंग से पुनर्वास के प्रयासों में मदद कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव स्तर पर निगरानी समितियां बनाकर पंचायतें नशे की आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रख सकती हैं। वे समय रहते कानून के क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को भी सतर्क करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और काम को बेहतर ढंग से करने के लिये जरूरी दिशा-निर्देश भी दिये जा सकते हैं। यह भी हकीकत है कि पेशेवर अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद के बिना गांवों की चुनी हुई संस्थाओं के द्वारा नशे की समस्या से पूरी तरह निपट पाना संभव नहीं है। इसके साथ ही सरकार को नशा-मुक्ति केंद्रों को सशक्त बनाने की भी जरूरत होगी। इसके अलावा नशे पर शिकंजा कसने के लिये जरूरी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए। वहीं दूसरी ओर नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे का सामना कर रहे युवाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी जरूरत होगी। यह भी कि मानसिक तनाव से मुक्ति के लिये मनोरंजन के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निस्संदेह, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के क्रम में हिमाचल सरकार का यह प्रयोग एक महत्वपूर्ण सच को सामने लाता है कि स्थायी बदलाव सरकारी दफ्तरों से नहीं बल्कि हकीकत में गांव से ही शुरू हो सकता है। जहां ग्रामीणों की सामूहिक जिम्मेदारी नशे की लत दूर करने के लिये एक मजबूत इलाज बन सकती है। यदि पंचायतों को पर्याप्त संसाधन व मदद मिले तो पंचायतें भी बदलाव लाने और मौजूदा पीढ़ी के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली ताकत बन सकती हैं।

अदालती फैसले के सामाजिक संकेतों को समझें

> "कोर्ट ने समाज को सोच बदलने को इशारा किया है। घर की जीवन रेखा स्त्री का मूल्य उस दिन तय नहीं होना चाहिए जब उसकी कमी खले। वास्तव में उसका मूल्य तो तभी से प्रतिष्ठा मिले, जब वह बिना पदनाम, वेतन और औपचारिक पहचान के घर को जीवंत करती हो।

कुछ फैसले अदालतों के रिकॉर्ड में दर्ज होकर खत्म नहीं होते। वे समाज की सोच में प्रवेश करते हैं और उन मान्यताओं को चुनौती देते हैं जिन्हें लंबे समय से सामान्य मान लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें सड़क दुर्घटना में एक गृहिणी की मृत्यु के मामले में घरेलू श्रम के आर्थिक मूल्य को स्वीकार किया गया, ऐसा ही फैसला है। पहली नजर में यह मामला महज मुआवजे के निर्धारण का लग सकता है, लेकिन इसकी असली गूंज उससे कहीं आगे जाती है। यह उस सामाजिक सोच पर सवाल उठाता है, जिसने घर के भीतर होने वाले महिलाओं के श्रम को प्रतिष्ठा नहीं दी। अदालत ने माना कि गृहिणी सही मायने में 'होममेकर' है। उसका श्रम उत्पादक है, उसका योगदान वास्तविक है और उसकी अनुपस्थिति का असर केवल भावनात्मक नहीं, आर्थिक और संरचनात्मक भी होता है। सवाल यह नहीं है कि अदालत ने घरेलू श्रम का आर्थिक मूल्य किस आधार पर तय किया। प्रश्न यह है कि जिस श्रम पर करोड़ों परिवार टिके हुए हैं, उसे श्रम मानने में हमें इतना समय क्यों लगा।

भारत में परिवार को एक संस्था के रूप में देखा गया है। उसकी स्थिरता, उसकी सामाजिक भूमिका और सांस्कृतिक महत्व पर लगातार बात होती रही है। लेकिन इस स्थिरता को बनाए रखने वाले श्रम पर उतनी गंभीर चर्चा नहीं हुई। घर चलाना केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं होता। यह समय प्रबंधन, संसाधनों का संतुलन, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक संबंधों का निर्वाह और परिवार की भावनात्मक संरचना को संभालने की निरंतर प्रक्रिया है। घर के भीतर होने वाला यह श्रम इसलिए अदृश्य हो जाता है क्योंकि वह बाजार के बाहर होता है। जिस काम के

लिए बाहर किसी को नियुक्त किया जाए तो उसका भुगतान तय होता है, वही काम जब घर के भीतर किया जाता है तो उसे जिम्मेदारी, प्रेम या संस्कार का विस्तार मान लिया जाता है। यहां समाज को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हमारे यहां लंबे समय तक एक सामान्य वाक्य चलता रहा, 'वह काम नहीं करती, घर संभालती है।' कथन के भीतर एक गहरी सामाजिक संरचना छिपी है।

सम्मान और मूल्य एक चीज नहीं हैं। सम्मान भावनात्मक हो सकता है, लेकिन मूल्य सामाजिक स्वीकृति का आधार बनता है। जिस योगदान को मूल्य नहीं मिलता, धीरे-धीरे उसकी भूमिका को स्वाभाविक मान लिया जाता है। फिर उसके पीछे का श्रम, समय और कौशल दिखाई देना बंद हो जाता है। विडंबना यह है कि परिवार की पूरी व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति अक्सर आर्थिक परिभाषाओं में 'निर्भर' माना जाता रहा। यह विरोधाभास सोच का भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी सोच को चुनौती देता है। निस्संदेह, अदालत के फैसले ने नुकसान की परिभाषा को नया अर्थ दिया।

अब तक जब किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी आय को परिवार की आर्थिक क्षति का आधार माना जाता था। लेकिन गृहिणी की मृत्यु के मामलों में यह तर्क दिया जाता रहा है कि उसकी प्रत्यक्ष आय नहीं थी, इसलिए आर्थिक नुकसान सीमित माना जाता है। वास्तव में किसी होममेकर की अनुपस्थिति केवल एक सदस्य की अनुपस्थिति नहीं होती। उसके साथ घर की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। बच्चों की दिनचर्या बदलती है, देखभाल की प्रणाली बदलती है, घरेलू खर्च का स्वरूप बदलता है और परिवार की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है।

यह फैसला बताता है कि हर वह काम जो वेतन में नहीं बदलता, वह मूल्यहीन नहीं होता। हालांकि, इस फैसले को महिलाओं के लिए वेतन की बहस तक सीमित करना भी उचित नहीं होगा। आज जब अर्थव्यवस्था, उत्पादकता और कार्यबल भागीदारी जैसे विषय चर्चा में हैं, तब यह स्वीकार करना जरूरी है कि सामाजिक पुनरुत्पादन, यानी परिवार का निर्माण और संचालन भी किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी शर्त है।

घर मनुष्य निर्माण की पहली संस्था होता है। यदि उस संस्था को चलाने वाले श्रम को लगातार अदृश्य रखा जाएगा तो बराबरी और सम्मान पर आधारित समाज की कल्पना अधूरी रहेगी। यह फैसला समाज को संबोधित करता है कि क्या हम अपने घरों में श्रम की बराबरी को समझते हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर अदालत नहीं दे सकती। समाज को खुद तय करना होगा कि वह इस फैसले को केवल मुआवजे के मामले का निर्णय मानता है या अपने समय के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत की तरह पढ़ता है। क्योंकि किसी होममेकर का मूल्य उस दिन तय नहीं होना चाहिए जब उसकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए। उसका मूल्य उस दिन पहचाना जाना चाहिए जब वह हर दिन बिना किसी पदनाम, वेतन और औपचारिक पहचान के घर को चलाने के लिए उपस्थित होती है।

किसी समाज की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह श्रम का कितना भुगतान करता है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति है, जिनकी उपस्थिति से घर केवल चलता नहीं बल्कि आकार लेता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी यही है। अदालत ने अपने हिस्से का निर्णय दे दिया है। अब समाज को अपने हिस्से का उत्तर देना है।

प्रेरणा

जहां संवेदना जीवित है, वहीं सच्ची सभ्यता है

मानव इतिहास को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि सभ्यता का विकास केवल भौतिक संसाधनों, तकनीकी प्रगति या विशाल निर्माणों की कहानी नहीं है। यह उतनी ही गहराई से मनुष्य की संवेदनाओं, उसके व्यवहार और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण की भी कहानी है। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं, वहां विज्ञान ने असंभव को संभव बना दिया है। मनुष्य समुद्र की गहराइयों को नाप चुका है, अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भविष्य की नई संभावनाओं का निर्माण कर रहा है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बीच एक प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों वर्ष पहले था—क्या हम वास्तव में अधिक सभ्य हुए हैं?

इस प्रश्न का उत्तर केवल आधुनिक सुविधाओं या आर्थिक विकास में नहीं मिलता। इसका उत्तर उस तरीके में छिपा है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। किसी समाज की वास्तविक पहचान इस बात से नहीं होती कि उसके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने कमजोर, असहाय और पीड़ित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यही वह कसौटी है जिस पर किसी भी सभ्यता की महानता को परखा जा सकता है।

एक प्रसिद्ध प्रसंग में मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड से पूछा गया कि किसी सभ्यता का पहला संकेत क्या माना जाना चाहिए। लोगों को उम्मीद थी कि वे किसी प्राचीन औजार, हथियार या कृषि व्यवस्था का उल्लेख करेंगी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी मानव जांघ की हड्डी का उदाहरण दिया जो कभी टूट गई थी और बाद में पूरी तरह जुड़ गई थी। उनका उत्तर सुनकर लोग चकित रह गए। तब उन्होंने समझाया कि जंगल में रहने वाले किसी भी जीव की टांग टूट जाए तो उसका जीवित बचना लगभग असंभव होता है। वह न तो भोजन प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन यदि किसी मनुष्य की टूटी हुई हड्डी ठीक हो गई, तो इसका अर्थ है कि किसी ने उसकी देखभाल की, उसे भोजन दिया, उसकी रक्षा की और उसके स्वस्थ होने तक उसका साथ निभाया। यही वह क्षण था जब मानवता ने सभ्यता की पहली सीढ़ी पर कदम रखा।

यह उदाहरण हमें बताता है कि सभ्यता का जन्म शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा से हुआ है। जब मनुष्य ने पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझा, तब उसने केवल सामाजिक जीवन की शुरुआत नहीं की, बल्कि मानवता की नींव भी रखी। यही भावना समाज को एकजुट करती है और उसे केवल लोगों का समूह न बनाकर एक समुदाय में परिवर्तित करती है।

आज के समय में विकास का अर्थ अक्सर ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, बड़ी अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक तकनीक से लगाया जाता है। निश्चित रूप से ये सभी किसी राष्ट्र की उन्नति के महत्वपूर्ण संकेत हैं। लेकिन यदि इनके बीच मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाएं, तो यह विकास अधूरा रह जाता है। कोई भी समाज कितना ही समृद्ध क्यों न हो, यदि वहां गरीबों की आवाज अनसुनी हो, वृद्ध उपेक्षित हों, बीमार असहाय हों और कमजोर लोग असुरक्षित महसूस करें, तो उस समाज को पूरी तरह सभ्य नहीं कहा जा सकता।

सभ्यता की असली परीक्षा संकट के समय होती है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जब किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटता है या जब समाज का कोई वर्ग कठिनाइयों का सामना करता है, तब यह देखा जाता है कि लोग एक-दूसरे के लिए कितना खड़े होते हैं। जो समाज अपने संकटग्रस्त लोगों को अकेला छोड़ देता है, वह चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो, उसकी आत्मा कमजोर होती है। इसके विपरीत जो समाज अपने सबसे कमजोर लोगों का हाथ थामता है, वही वास्तव में मजबूत और महान कहलाता है।

भारतीय संस्कृति ने सदैव करुणा को जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना है। यहां दया, सेवा और परोपकार को धर्म का आधार माना गया है। हमारे संतों और महापुरुषों ने हमेशा यह संदेश दिया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदनशीलता है। भगवान बुद्ध ने करुणा को मुक्ति का मार्ग बताया, महावीर ने प्रत्येक जीव के प्रति दया का संदेश दिया और संत कबीर ने प्रेम को जीवन का सार कहा। इन शिक्षाओं का मूल भाव यही है कि मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता विकसित न करे।

वर्तमान समय में दुनिया कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तकनीक ने हमें भौतिक रूप से जोड़ दिया है, लेकिन कई बार भावनात्मक रूप से हम पहले से अधिक अकेले दिखाई देते हैं। ऐसे समय में करुणा और संवेदनशीलता की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। यदि हम केवल अपनी सफलता, अपने लाभ और अपने आराम के बारे में सोचते रहेंगे, तो समाज में संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा।

करुणा का अर्थ केवल दान देना या किसी की आर्थिक सहायता करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को समझना और उसके प्रति सहानुभूति रखना। कभी-कभी एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान, एक सहयोगी व्यवहार या कठिन समय में दिया गया भावनात्मक सहारा भी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ऐसे छोटे-छोटे कार्य ही समाज में विश्वास और मानवता को जीवित रखते हैं।

यह भी सच है कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है, उसका जीवन अधिक संतुलित और संतुष्ट होता है। वह केवल उपलब्धियों की दौड़ में नहीं जीता, बल्कि रिश्तों और मानवीय मूल्यों को भी महत्व देता है। यही दृष्टिकोण उसे एक बेहतर इंसान बनाता है और समाज को भी बेहतर दिशा देता है।

आज जब दुनिया प्रगति के नए अध्याय लिख रही है, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अभी भी वही है जो हजारों वर्ष पहले था—मानवता। मशीनें तेज हो सकती हैं, तकनीक उन्नत हो सकती है और शहर अधिक आधुनिक हो सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य के हृदय से करुणा समाप्त हो जाए तो सारी उपलब्धियां अपना अर्थ खो देती हैं। सभ्यता का वास्तविक सौंदर्य पत्थरों की इमारतों में नहीं, बल्कि उन हृदयों में बसता है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। अंततः किसी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति की महानता उसकी बाहरी चमक-दमक से नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशीलता से मापी जानी चाहिए।

जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका दिखा अलग थलग, दुनिया जता रही मोदी पर भरोसा

जी-7 शिखर सम्मेलन इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार का मंच नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का आईना प्रतीत हुआ। फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनके सामने वह यूरोप खड़ा था जो अब आंख मूंदकर वॉशिंगटन के पीछे चलने को तैयार नहीं दिखता। लंबे समय तक टैरिफ की धमकियां, कूटनीतिक दबाव, सार्वजनिक अपमान और अचानक फैसलों का सामना करने के बाद अब यूरोपीय देशों ने यह मान लिया है कि ट्रंप बदलती अमेरिकी सोच का स्थायी चेहरा हैं। यही कारण है कि इस बार जी-7 सम्मेलन पर सबसे गहरी छाया अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दूरी की रही। देखा जाये तो ईरान युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक बेचैनी ने इस सम्मेलन को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई को लेकर चिंता गहरा रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के मोड में पहुंचती दिखाई दे रही है। ट्रंप इस सम्मेलन में यह साबित करने पहुंचे कि उनकी आक्रामक और टकराव वाली विदेश नीति परिणाम दे रही है। वह चाहते हैं कि दुनिया अमेरिकी प्राथमिकताओं को स्वीकार करे, चाहे मामला व्यापार का हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, सुरक्षा का या फिर चीन को घेरने की रणनीति का। लेकिन इस बार यूरोप का स्वर बदला हुआ है। वह अमेरिका के साथ तो रहना चाहता है, मगर उसकी हर बात पर सिर झुकाने को तैयार नहीं है। देखा जाये तो यूरोप के भीतर यह बदलाव अचानक नहीं आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों वर्षों से यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क साफ है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहे मैक्रों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह ऐसा समय है जब अमेरिकी, रूसी और चीनी नेतृत्व यूरोप के हितों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। इसलिए यूरोप को अब जागना होगा और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। हालांकि मैक्रों की रणनीति केवल विरोध की नहीं है। उन्होंने ट्रंप के साथ निजी संबंध बनाए रखने की भी भरपूर कोशिश की है। कभी एफिल टावर पर भोज, कभी सैन्य परेड में विशेष सम्मान और कभी नोट्रे डेम कैथेड्रल के पुनरोद्धार समारोह में आमंत्रण देकर उन्होंने ट्रंप को साधने की कोशिश की है। लेकिन ईरान युद्ध और ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप में ट्रंप विरोध चरम पर पहुंच गया। एक समय तो हालात ऐसे बन गए थे कि यूरोपीय नेताओं को लगने लगा कि ट्रंप डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना भेज सकते हैं। यह केवल एक भू-राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि उस भरोसे के टूटने का प्रतीक था जिस पर दशकों से अटलांटिक गठबंधन टिका हुआ था।

दरअसल, ग्रीनलैंड प्रकरण ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं नाटो की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। यही कारण है कि अब यूरोपीय देशों में यह बहस तेज हो गई है कि अगर अमेरिका हर वैश्विक संकट में नेतृत्व नहीं करता या करना नहीं चाहता, तो आगे की दुनिया कैसी होगी। इस चिंता ने नाटो और अटलांटिक गठबंधन की नींव तक को हिला दिया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी इस बार दबाव में दिखे। घरेलू राजनीति में चुनौती झेल रहे स्टारमर को ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन न करने के कारण ट्रंप की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटेन का मजाक उड़ाया और उसे असहयोगी तक कह दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्रेक्जिट के बाद अमेरिका के और करीब जाने की कोशिश कर रहा ब्रिटेन अब फिर यूरोप की ओर झुकता दिखाई दे रहा है।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें कभी ट्रंप का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता था, वह भी अब दूरी बनाती नजर आ रही हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुईं और उन्होंने अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिम एशिया के बीच संवाद की कड़ी बनने की कोशिश की। साफ है कि दुनिया अब केवल अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर रहने की बजाय बहुध्रुवीय संतुलन की तरफ बढ़ रही है। देखा जाये तो ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि वह निजी कूटनीति को सार्वजनिक तमाशे में बदल देते हैं। पिछले वर्ष नाटो प्रमुख मार्क रुटे के निजी संदेश सार्वजनिक कर उन्होंने यह दिखा दिया था कि यूरोपीय नेता निजी तौर पर अमेरिका के दबाव को स्वीकार करते हैं, भले ही सार्वजनिक मंचों पर विरोध का अभिनय करें। इस कारण अब यूरोपीय नेताओं के लिए संतुलन साधना और मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने मतदाताओं को भी संतुष्ट रखना है और अमेरिका से रिश्ते भी नहीं बिगाड़ने हैं। इसी उथल पुथल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस सम्मेलन में विशेष महत्व रखती है। जब पश्चिमी दुनिया भीतर से विभाजित दिखाई दे रही है, तब भारत एक ऐसे संतुलित और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है जिस पर हर शक्ति केंद्र भरोसा करना चाहता है। मोदी ने रूस और अमेरिका दोनों से संबंध बनाए रखे, पश्चिम एशिया के संकटों में संतुलन साधा और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिर नेतृत्व वाली निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है। देखा जाये तो मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने भारत को किसी एक खेमे में सीमित नहीं होने दिया। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी भी कायम रखी और रूस के साथ पुराने रिश्ते भी नहीं टूटने दिए। पश्चिम एशिया में भारत की स्वीकार्यता बनी रही और यूरोप के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग भी लगातार बढ़ता गया। जी-7 जैसे मंचों पर मोदी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत केंद्र में आ चुका है। जब दुनिया अविश्वास, टकराव और अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत संवाद, संतुलन और स्थिरता का चेहरा बनकर उभरा है।

अभियान

अयोध्या की चौखट के प्रहरी: क्यों रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाना माना जाता है अनिवार्य?

अयोध्या केवल एक नगर नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का जीवंत केंद्र है। सरयू के पावन तट पर बसी यह नगरी भगवान श्रीराम की जन्मभूमि होने के कारण सदियों से श्रद्धा का केंद्र रही है। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के दर्शन की इच्छा लेकर आता है, लेकिन अयोध्या की एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। यह परंपरा है रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने की। माना जाता है कि जब तक भक्त हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता, तब तक उसकी अयोध्या यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यही कारण है कि अयोध्या पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु सबसे पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं।

हनुमानगढ़ी केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह उस अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है जो हनुमान जी और भगवान श्रीराम के बीच विद्यमान था। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है और वहां पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे-जैसे श्रद्धालु इन सीढ़ियों को पार करते हैं, वैसे-वैसे उनके मन में भक्ति और उत्साह का भाव बढ़ता जाता है। मंदिर के शिखर पर पहुंचते ही भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। घंटियों की मधुर ध्वनि, जय श्रीराम और जय बजरंगबली के गूंजते जयकारे तथा भक्तों की अटूट श्रद्धा वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देती है।

हनुमानगढ़ी के महत्व के पीछे एक अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण करके माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। लोगों ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। इसके बाद समय आने पर श्रीराम ने अपने साथियों, मित्रों और सहयोगियों को सम्मानपूर्वक विदा करना शुरू किया। सभी अपने-अपने स्थानों को लौट गए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसका मन अयोध्या छोड़ने को तैयार नहीं था। वह थे रामभक्त हनुमान।

हनुमान जी के लिए भगवान श्रीराम केवल राजा या ईश्वर नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य थे। उनका प्रत्येक श्वास राम नाम को समर्पित था। जब श्रीराम ने उनसे वापस जाने के लिए कहा, तब हनुमान जी का हृदय व्याकुल हो उठा। वे प्रभु से दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी निस्वार्थ भक्ति और अथाह प्रेम को देखकर भगवान श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या में ही रहने के लिए एक विशेष स्थान प्रदान किया। यह स्थान एक ऊंचे टीले पर स्थित था, जहां से संपूर्ण अयोध्या नगरी पर दृष्टि रखी जा सकती थी।

मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने हनुमान जी से कहा कि वे इस स्थान पर रहकर अयोध्या की रक्षा करें और आने वाले भक्तों को आशीर्वाद दें। साथ ही उन्होंने एक विशेष वचन भी दिया कि जो भक्त अयोध्या में उनके दर्शन के लिए आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वह पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन न कर ले। यही कारण है कि आज भी करोड़ों श्रद्धालु इस परंपरा का पालन करते हैं और रामलला के दर्शन से पहले बजरंगबली के चरणों में शीश झुकाते हैं।

धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार हनुमानगढ़ी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि अयोध्या की सुरक्षा का आध्यात्मिक केंद्र भी है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पवित्र नगरी के अदृश्य रक्षक के रूप में यहां विराजमान हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में उन्होंने श्रीराम की सेवा की थी, उसी प्रकार आज भी वे अयोध्या और वहां आने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि हनुमानगढ़ी पहुंचते ही उन्हें एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो बजरंगबली स्वयं अपने भक्तों की पीड़ा सुन रहे हों और उन्हें मानसिक बल प्रदान कर रहे हों।

हनुमानगढ़ी से जुड़ी एक और विशेष बात इसकी मुख्य प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह में माता अंजनी की गोद में विराजमान बाल हनुमान की अत्यंत मनोहारी प्रतिमा स्थापित है। यह स्वरूप भक्तों को वात्सल्य, प्रेम और भक्ति का संदेश देता है। सामान्यतः हनुमान जी को वीर, पराक्रमी और बलशाली रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां उनका बाल स्वरूप श्रद्धालुओं के मन में विशेष भाव उत्पन्न करता है। माता की गोद में बैठे बाल हनुमान यह संदेश देते हैं कि शक्ति और विनम्रता का सुंदर संगम ही सच्चे जीवन का आधार है।

धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां आने वाले भक्त अपनी विभिन्न मनोकामनाओं के साथ बजरंगबली के चरणों में उपस्थित होते हैं। कोई संतान प्राप्ति की कामना करता है, कोई रोगमुक्ति की, कोई रोजगार की तो कोई पारिवारिक सुख-शांति की। विश्वास किया जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की हर उचित इच्छा को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि देश के कोने-कोने से लाखों लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

हनुमानगढ़ी में चोला चढ़ाने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। श्रद्धालु सिंदूर, चमेली का तेल और विशेष वस्त्र अर्पित कर हनुमान जी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे ग्रह दोष, भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की विभिन्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन दिनों मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिलता है।

हनुमानगढ़ी का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य ने कराया था। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के अनेक प्राचीन धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार कराया था और उन्हें नई पहचान दी थी। समय के साथ मंदिर में कई बार जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ, लेकिन इसकी आध्यात्मिक महिमा आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी सदियों पहले थी।

अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इस आधुनिक युग में भी हनुमानगढ़ी की परंपरा और महत्ता में कोई कमी नहीं आई है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाला लगभग हर भक्त पहले हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि उस अमर संबंध का प्रतीक है जो राम और हनुमान के बीच विद्यमान था।

हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा संदेश निस्वार्थ सेवा है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन केवल प्रभु की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। हनुमानगढ़ी इसी आदर्श का जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाला प्रत्येक भक्त यह अनुभव करता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि समर्पण, सेवा, विनम्रता और कर्तव्य पालन में भी प्रकट होती है।

आज भी जब कोई श्रद्धालु हनुमानगढ़ी की 76 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंचता है और बाल हनुमान के दर्शन करता है, तो उसके मन में एक अनोखी शांति का संचार होता है। वह केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं करता, बल्कि उस अमर कथा का हिस्सा बन जाता है जिसमें एक भक्त ने अपने प्रभु के प्रति प्रेम की ऐसी मिसाल स्थापित की, जो युगों-युगों तक स्मरणीय रहेगी। यही कारण है कि अयोध्या की यात्रा में हनुमानगढ़ी केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि वह पवित्र द्वार है जहां से होकर भक्त भगवान श्रीराम के दर्शन की ओर अग्रसर होता है। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन का मार्ग हनुमानगढ़ी से होकर ही गुजरता है, क्योंकि जहां राम हैं, वहां हनुमान हैं और जहां हनुमान हैं, वहीं सच्ची भक्ति का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सुदूरवर्ती व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अब और अधिक तेज तथा सरल होगी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : राज्य में पहली बार टू-व्हीलर हेल्थ यूनिट सेवाओं का शुभारंभ हुआ

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 51 टू-व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट तथा 9 नई मोबाइल हेल्थ यूनिट को फ्लैग ऑफ करवाया

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया की उपस्थिति में सभी मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को 14 जिलों के लिए रवाना किया गया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को राज्य के आदिजाति क्षेत्रों में सुदूरवर्ती व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए राज्य में पहली बार 51 टू-व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का शुभारंभ करवाया ।

मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया की उपस्थिति में गांधीनगर से इन 51 टू-व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट और 9 नई मोबाइल हेल्थ वैन यूनिट को फ्लैग ऑफ कर 14 जिलों के लिए रवाना किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने होलिस्टिक हेल्थकेयर का जो दृष्टिकोण देश में अपनाया है; उसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में साकार करने के उद्देश्य से राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदिजाति तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की है।

51 टू-व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट और 9 नई मोबाइल हेल्थ यूनिट सेवाओं का मुख्य उद्देश्य दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय पर और सहज रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना है।

राज्य के उन दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फोर-व्हीलर वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां आपातकालीन अथवा आवश्यकता के समय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इन 51 टू-व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

इन यूनिट्स में आवश्यक दवाओं तथा प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों से युक्त मेडिकल बॉक्स की सुविधाएं होंगी।

इतना ही नहीं; डिजिटल बीपी मशीन, स्टेथोकोप, ग्लूकोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, हीमोग्लोबिन मीटर, नी-हैमर, नीडल कटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, टॉर्च सहित आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। साथ ही निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल डेटा एंट्री को सीएम डैशबोर्ड के साथ संकलित किया गया है।

इन नई सेवाओं से आदिजाति समुदाय को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा सकेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन और उपचार उपलब्ध होने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सफलता मिलेगी; कुल मिलाकर माता और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

इस नई पहल से समय पर निदान, उपचार तथा विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए त्वरित रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, मलेरिया तथा मूत्र संबंधी प्राथमिक जांचें ग्रामीण स्तर पर ही की जा सकेंगी। रोगों की प्रारंभिक पहचान और समय पर उपचार संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त गंभीर अथवा विशेष उपचार की आवश्यकता वाले मरीजों को निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में समय पर रेफर किया जाएगा, जिससे उन्हें उचित उपचार प्राप्त करने में सरलता होगी।

इस सेवा के अंतर्गत किशोरियों तथा महिलाओं के विशेष देखभाल के लिए एनीमिया, पोषण, किशोर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इससे स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। हेल्थ अवेयरनेस अंतर्गत एचआईवी/एड्स, तंबाकूजनित रोगों, संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इन यूनिट्स के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग तथा तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर से ही की जा सकेगी।

नई लोकार्पित की गई इन 51 टू-व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और 9 नई मोबाइल हेल्थ यूनिट्स द्वारा आदिजाति एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं घर के निकट उपलब्ध होंगी, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'हेल्थ केयर फॉर ऑल' का संकल्प साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देश में गुजरात सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम ग्रामीण और आदिजाति समाज के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के 'लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी' के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएगा तथा स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मोबाइल यूनिट्स प्रस्थान के इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. रतन चारण गढवी, अपर निदेशक डॉ. नीलम पटेल तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय रेल ने गुजरात में 493 करोड़ की आदिपुर-भुज डबलिंग परियोजना को दी मंजूरी

कच्छ क्षेत्र में रेल संपर्क और क्षमता विस्तार को मिलेगा नया आयाम,दोनों दिशाओं में प्रतिदिन दो अतिरिक्त यात्री रेल सेवाओं के संचालन का मार्ग होगा प्रशस्त,डबल लाइन से प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक संपर्क को मिलेगा बल

भारतीय रेल ने गुजरात में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पश्चिम रेलवे के आदिपुर-भुज रेलखंड (49 किलोमीटर) के दोहरीकरण कार्य को 493 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की है। मण्डल रेल प्रबंधक (DRM) अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने बताया कि यह परियोजना भारतीय रेल द्वारा नेटवर्क क्षमता विस्तार हेतु चलाए जा रहे डबलिंग, ट्रिपलिंग एवं अन्य आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस रेलखंड के दोहरीकरण से कच्छ क्षेत्र में रेल संपर्क और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा भविष्य में यात्री एवं माल यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

बढ़ते यातायात के मद्देनज़र क्षमता विस्तार

गांधीधाम-नलिया कॉरिडोर पर स्थित आदिपुर-भुज खंड वर्तमान में सिंगल रेल लाइन है। क्षेत्र में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद इस खंड पर यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इनमें भुज-नलिया गेज परिवर्तन, नलिया-वायोर लाइन विस्तार तथा नलिया-जखाऊ, वायोर-लखपत एवं देशलपर-लूना नई रेल लाइन परियोजनाएं शामिल हैं।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद भुज-आदिपुर खंड पर अतिरिक्त यात्री और माल यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए इस रेलखंड के दोहरीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ परिचालन दक्षता में भी सुधार होगा।

यात्री एवं माल परिवहन को मिलेगा लाभ

इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद दोनों दिशाओं में प्रतिदिन दो अतिरिक्त यात्री रेल सेवाओं का संचालन संभव हो सकेगा, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर संपर्क और यात्रा सुविधाएं प्राप्त होंगी।

डबल लाइन के निर्माण से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 12 मिलियन टन (MTPA) माल यातायात का संचालन संभव होगा, जिससे पश्चिम गुजरात में लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होगा।

भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा क्षमता विस्तार

वर्तमान में इस रेलखंड की लाइन क्षमता उपयोगिता लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2029-30 तक इसके 123 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में समय रहते क्षमता विस्तार अत्यंत आवश्यक हो गया है। डबलिंग परियोजना से रेलमार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी, परिचालन संबंधी बाधाएं घटेंगी तथा रेल सेवाओं की समयबद्धता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

इस परियोजना से यात्री एवं माल यातायात में वृद्धि के माध्यम से भारतीय रेल की आय में भी बढ़ोतरी होगी तथा कच्छ क्षेत्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

इस परियोजना की स्वीकृति के साथ भारतीय रेल भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक और सक्षम रेल अवसंरचना विकसित करने, संपर्क बढ़ाने तथा राष्ट्रीय रेल नेटवर्क की क्षमता में निरंतर वृद्धि करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रही है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने किया पालनपुर-सामाख्याली रेलखंड का गहन निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने आज 17.06.2026 को अहमदाबाद मंडल के पालनपुर-सामाख्याली रेलखंड का व्यापक निरीक्षण किया। इस उच्च स्तरीय निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन में सुरक्षा और संरक्षा को सुदृढ़ करना, बुनियादी ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) कार्यों की प्रगति को परखना तथा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं व अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करना था। इस अवसर पर उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश, मुख्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष (PHODs) तथा अहमदाबाद मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

न्यू पालनपुर स्टेशन पर रनिंग स्टाफ और लॉबी का निरीक्षण:

निरीक्षण की शुरुआत में महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने न्यू पालनपुर स्टेशन पर क्रू लॉबी और रनिंग रूम का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने वहाँ स्थापित क्रू मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया। महाप्रबंधक ने ड्यूटी पर तैनात रनिंग स्टाफ (लोको पायलट और गार्ड) से सीधे संवाद कर उन्हें मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया, जिस पर स्टाफ ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने बेस किचन, शौचालयों तथा परिसर की अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

अमृत स्टेशन योजना और यात्री सुविधाओं की समीक्षा:

अपने दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने 'अमृत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे पालनपुर स्टेशन के कार्यों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर पेयजल (वॉटर टैप), प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम), फूड स्टॉल, फुट ओवर ब्रिज (FOB), प्लेटफॉर्म और अंडरपास सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और पूरे स्टेशन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति की व्यापक समीक्षा की।

ट्रैक और सुरक्षा मानकों का गहन निरीक्षण:

संरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए महाप्रबंधक ने पालनपुर से सामाख्याली के बीच रेल पटरी (रेलवे ट्रैक), लेवल क्रॉसिंग फाटकों, महत्वपूर्ण एवं छोटे पुलों, पॉइंट्स, सेक्शन में आने वाले मोड़ों (कर्व्स) और क्रॉसिंग का गहन तकनीकी निरीक्षण किया। उन्होंने खिड़की निरीक्षण (विंडो ट्रेलिंग) के माध्यम से सुरक्षा मानकों को परखा और संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न संरक्षा पहलुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

भीलड़ी और लाकड़िया स्टेशनों पर विकास कार्यों का जायजा:

महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने भीलड़ी स्टेशन पर स्टेशन रिडवलपमेंट कार्य की वर्तमान प्रगति, यात्री सुविधाओं, रनिंग रूम और क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। यहाँ भी उन्होंने रनिंग स्टाफ के भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की।

लाकड़िया रेलवे स्टेशन उन्होंने स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI) रूम और स्टेशन मास्टर केबिन का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण (ARME) व प्लेटफॉर्म आदि का निरीक्षण किया और यात्रियों की सहूलियत के लिए हर संभव सुधार करने के निर्देश दिए।

सामाख्याली स्टेशन का निरीक्षण एवं व्यापारियों के साथ बैठक

महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने अहमदाबाद मंडल के प्रथम पुनर्विकसित सामाख्याली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जायजा लिया तथा मास्टर केबिन, फूड स्टॉल, प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम), बुकिंग काउंटर सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया और यात्रियों से संवाद भी किया। उन्होंने रेलवे कॉलोनी का दौरा कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

इस दौरान महाप्रबंधक ने नमक व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें क्षेत्र से होने वाली माल ढुलाई (लोडिंग) बढ़ाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2029-30 तक 200 मिलियन टन माल लदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। अहमदाबाद मंडल को चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 4 मिलियन टन लोडिंग का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में व्यापारियों से सुझाव प्राप्त किए गए तथा रेल परिवहन के माध्यम से नमक लदान को और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। व्यापारियों ने बताया कि मंडल के अधिकारियों से उन्हें निरंतर अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर गांधीधाम के एरिया मैनेजर श्री आशीष धानिया सहित रेलवे के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

केंद्र सरकार ने डॉक्टर के पर्चे के बिना खांसी की दवा सहित सिरप वाली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश भर में बेची जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर के पर्चे के बिना खांसी की दवा सहित सिरप की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इस कदम का उद्देश्य खांसी की दवा सहित सिरप आधारित उत्पादों को नियामक निगरानी में लाना है। यह संशोधन औषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यह संशोधन प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K के "दवाओं की श्रेणी" कॉलम में मद 7 से "सिरप" शब्द को हटा दिया गया है। अनुसूची K उन दवाओं की श्रेणियों को संदर्भित करती है जिन्हें औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और नियमों के तहत निर्माण, बिक्री और वितरण से संबंधित कुछ प्रावधानों से निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

यह कदम पिछले साल दिसंबर में सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के मसौदे के बाद उठाया गया है, जिसमें हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। मंत्रालय ने कहा कि दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर देश की सर्वोच्च वैधानिक संस्था, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) से परामर्श के बाद संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले जनता से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया था। यह निर्णय हाल के वर्षों में कई देशों में बच्चों की जहर से संबंधित मौतों की खबरों के बाद खांसी की चाशनी और अन्य तरल मौखिक दवाओं की नियामक जांच के मद्देनजर आया है। सूत्रों के अनुसार, नवीनतम संशोधन निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा सख्त लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करके चाशनी-आधारित दवाओं की ट्रेसबिलिटी और नियामक निगरानी को बढ़ाएंगे।

नीट परीक्षा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु भावनगर गांधीग्राम के मध्य विशेष ट्रेन का संचालन

यात्रियों तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर भावनगर–गांधीग्राम–भावनगर के मध्य विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 09254 भावनगर टर्मिनस–गांधीग्राम स्पेशल दिनांक 20 जून, 2026 (शनिवार) को भावनगर टर्मिनस से 11:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा भावनगर परा, सिहोर जंक्शन, धोला जंक्शन, बोटाद जंक्शन, धंधुका, धोलका, बावला एवं सरखेज स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 16:10 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09253 गांधीग्राम–भावनगर टर्मिनस स्पेशल दिनांक 21 जून, 2026 (रविवार) को गांधीग्राम से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उपरोक्त स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए रात्रि 00:35 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 24 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 20 सेकेंड क्लास स्लीपर कोच, 02 जनरल कोच तथा 02 एसएलआर/डी कोच शामिल होंगे। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों एवं नीट परीक्षा अभ्यर्थियों से इस विशेष रेल सेवा का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं टिकट बुकिंग संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, एनटीईएस अथवा निकटतम रेलवे स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं।

अहमदाबाद मंडल ने ओएचई की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक अपनाई, सुरक्षा को मिलेगा नया बल

AI-सक्षम हवाई निरीक्षण से बिना बाधा उत्पन्न किए ओएचई की गंभीर खामियों का पता लगाने में मिली सफलता, रखरखाव होगा और बेहतर

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की जांच के लिए ड्रोन से हवाई निरीक्षण का सफल परीक्षण किया है। यह भारतीय रेल में नई तकनीक के जरिए सुरक्षित रखरखाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रैल 2026 में आरडीएसओ के निर्देश संख्या TI/IN/0060 को मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम रेलवे इस तकनीक का उपयोग शुरू करने वाले प्रमुख जोनों में शामिल हो गया है। 8 जून 2026 को किए गए इस परीक्षण से पारंपरिक मैनुअल जांच की जगह आधुनिक और सुरक्षित व्यवस्था की ओर बढ़ने का रास्ता खुला है।

ड्रोन से ओएचई का हवाई निरीक्षण

डीजीसीए के मानकों के अनुसार हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और जियो-टैगिंग सुविधा वाले ड्रोन की मदद से अहमदाबाद मंडल की टीम ने मास्ट संख्या 493-494 के बीच ओएचई संरचनाओं का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मिली हर खराबी की तस्वीर ली गई, उसे जीपीएस लोकेशन के साथ दर्ज किया गया और उसकी गंभीरता का आकलन किया गया। इससे जरूरी मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा।

यह निरीक्षण आरडीएसओ द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश (TI/IN/0060) के अनुसार किया गया। इन दिशा-निर्देशों में डीजीसीए से मान्यता प्राप्त ड्रोन, जीपीएस/जीएनएसएस, जियो-टैग्ड तस्वीरें और थर्मल स्कैनिंग जैसी सुविधाओं का प्रावधान है।

समय रहते मिली कई गंभीर खराबियां

परीक्षण के दौरान कई तरह की खराबियां सामने आईं। इनमें इंसुलेटरों पर फ्लैश मार्क, कैंटिलीवर पर लटकी बाहरी सामग्री, पोर्टल संरचनाओं और कैंटिलीवर पर बने पक्षियों के घोंसले तथा वहां बैठे पक्षी शामिल थे। इसके अलावा कैटेनरी स्ट्रैंड में नुकसान जैसी गंभीर खराबियां भी मिलीं, जिन्हें सामान्य जांच के दौरान पहचानना मुश्किल होता है।

ड्रोन से ली गई साफ और जियो-टैग्ड तस्वीरों की मदद से इन खराबियों का सही स्थान पता चला। इससे समय पर मरम्मत कर भविष्य में ओएचई ट्रिपिंग, बिजली आपूर्ति में रुकावट और अन्य परिचालन समस्याओं को रोका जा सकेगा।

स्मार्ट जांच से रेलवे होगी और सुरक्षित

25 केवी एसी बिजली देने वाली ओएचई प्रणाली भारतीय रेल के विद्युतीकृत नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसुलेटर, कंडक्टर, क्लैंप या अन्य उपकरणों में खराबी आने से ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है और सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं। पारंपरिक जांच के लिए ट्रैक ब्लॉक लेना पड़ता है और कर्मचारियों को हाई वोल्टेज उपकरणों के पास काम करना पड़ता है। जबकि ड्रोन की मदद से बिना ट्रैक ब्लॉक लिए तेजी से कई स्थानों की जांच की जा सकती है और अलग-अलग कोणों से तस्वीरें ली जा सकती हैं। इससे जांच का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है और रखरखाव का काम अधिक व्यवस्थित होता है।

भविष्य में एआई आधारित विश्लेषण की तैयारी

पश्चिम रेलवे इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अभी जांच प्रक्रिया को मजबूत करने और बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। भविष्य में यही डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे खराबियों का पहले से पता लगाया जा सकेगा और संभावित जोखिमों को समय रहते रोका जा सकेगा। इससे ओएचई रखरखाव प्रणाली और अधिक आधुनिक तथा पूर्वानुमान आधारित बन सकेगी।

राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया परीक्षण

यह परीक्षण रेलवे बोर्ड (एम/टीआरएस) के पत्र संख्या 2024/EEM/148/4 Part IV E-3479194 दिनांक 24.04.2026 तथा आरडीएसओ, लखनऊ द्वारा जारी निर्देश संख्या TI/IN/0060 के अनुसार किया गया। इन दिशा-निर्देशों में ड्रोन, कैमरा प्रणाली, डेटा सुरक्षा और निरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े मानक तय किए गए हैं।

पश्चिम रेलवे भविष्य में इस तकनीक का विस्तार पूरे जोन में, जिसमें उपनगरीय रेल नेटवर्क भी शामिल है, चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बना रहा है। यह पहल भारतीय रेल के विद्युतीकृत नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अहमदाबाद मेडिसिटी में अनुमानित 295 करोड़ रुपए की लागत से साकार होंगे विश्व स्तरीय 'स्पाइन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर तथा रिहेबिलिटेशन सेंटर' : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया

▸▸ वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ तथा 2036 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर वर्तमान तथा भावी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात सज्ज : स्वास्थ्य राज्य मंत्री

▸▸ स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने पिछले तीन वर्ष में स्पाइन सर्जरी में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आने पर अभिनंदन दिया

▸▸ 'स्पाइन एवं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर' आयोजन-प्रगति को लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया की अध्यक्षता में गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक

गांधीनगर : स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा है कि गुजरात में मेरुदंड (रीढ़)-स्पाइन के रोगों की बढ़ती संख्या से निपटने तथा आगामी वैश्विक खेल-कूद महोत्सवों को ध्यान में रखकर अहमदाबाद मेडिसिटी में लगभग 295 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सज्ज स्पाइन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।

इस प्रोजेक्ट के आयोजन एवं प्रगति को लेकर बुधवार को गांधीनगर में श्री पानशेरिया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई; जिसमें गवर्नमेंट स्पाइन इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. पीयूष मित्तल, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में विस्तार से जानकारी देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गुजरात वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ तथा 2036 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा एवं पुनर्वास सुविधाएँ राज्य में ही मुहैया कराने में यह इंस्टीट्यूट वरदान सिद्ध होगा। समग्र आयोजन की रूपरेखा देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल उपचार देना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात को स्पोर्ट्स मेडिसीन और स्पाइन केयर का ग्लोबल हब बनाना है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने पिछले तीन वर्षों में गुजरात में स्पाइन सर्जरी में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आने पर अभिनंदन दिया।

उन्होंने आगे कहा कि इस परिसर में सुपर-स्पेशलिस्ट मानव बल तैयार करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और स्पाइन व स्पोर्ट्स मेडिसीन क्षेत्र में विश्वस्तरीय अनुसंधान के लिए विशेष व्यवस्थाएँ भी विकसित की जाएंगी, जिससे भविष्य में देश-विदेश के विशेषज्ञ यहाँ अपनी सेवाओं और ज्ञान का लाभ दे सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित परिसर में स्पाइन संबंधी रोगों तथा खेल-कूद संबंधी चोटों के सटीक निदान, उपचार तथा पुनर्वास की सभी आधुनिक सुविधाएँ एक ही स्थल पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट में जटिल स्पाइन सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वर्ल्ड क्लास रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएँ दी जाएंगी।

श्री पानशेरिया ने बैठक में प्रोजेक्ट की समयसीमा तय करने, गुणवत्तायुक्त तथा त्वरित कार्य करने के लिए पीआईयू और विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष: पीएम गतिशक्ति से गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, रिकॉर्ड समय में हो रहा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

▸▸ 22 विभागों और मंत्रालयों के समन्वय से 11,000 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी NOC रिकॉर्ड समय में प्रोसेस्ड

▸▸ देश का पहला 'डिजिटल रिज़र्वयर मैनेजमेंट सिस्टम' गुजरात में लागू

▸▸ 83,000 हैंडपंपों की जियो-टैगिंग और देश के पहले 'डिजिटल रिज़र्वयर मैनेजमेंट सिस्टम' से नागरिक सेवाओं में बड़ा बदलाव

▸▸ जंबूसर के 3,900 करोड़ के बल्क ड्रग पार्क की संपूर्ण प्लानिंग पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पर तैयार

गांधीनगर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के साथ 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा बदलने वाली एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने इस पहल को तकनीक आधारित सुशासन के प्रभावी मॉडल में बदल दिया है। वर्षों तक विभागीय मंजूरियों और कागजी प्रक्रियाओं में उलझने वाली परियोजनाएँ अब एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड समय में आगे बढ़ रही हैं।

40 इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी NOC प्रक्रियाएँ एकीकृत, 11,000 से अधिक NOC मंजूरियाँ रिकॉर्ड समय में प्रोसेस्ड

गुजरात ने BISAG-N द्वारा विकसित GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर NOC मंजूरी प्रक्रिया को पूरी तरह आधुनिक और तकनीक आधारित बना दिया है। 'मेकर-चेकर-अप्रूवर' मॉडल, ई-अप्रूवल सिस्टम और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं के जरिए 40 इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी NOC प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल फ्रेमवर्क से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक 11,000 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी NoC रिकॉर्ड समय में प्रोसेस किया जा रहा हैं।

इस डिजिटल व्यवस्था ने मंजूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह बनाया है। मैनुअल फाइल मूवमेंट लगभग समाप्त हो चुका है, विभागों के बीच समन्वय पहले से अधिक मजबूत हुआ है और परियोजनाओं को योजना से क्रियान्वयन तक पहुँचाने की गति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

2,900 से अधिक डेटा लेयर्स का इन्टीग्रेशन और 2,400 से अधिक परियोजनाओं की हुई रियल-टाइम GIS मैपिंग

पीएम गतिशक्ति के तहत गुजरात ने 1,500 से अधिक राज्य स्तरीय तथा 1,400 से अधिक केंद्रीय डेटा लेयर्स सहित कुल 2,900 से अधिक डेटा लेयर्स को एकीकृत कर 2,400 से अधिक आगामी एवं क्रियान्वयनाधीन

परियोजनाओं की GIS आधारित रियल-टाइम मैपिंग की है। इनमें नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग की 858, ऊर्जा क्षेत्र की 795, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग की 422 तथा शहरी विकास विभाग की 242 परियोजनाएँ शामिल हैं।

API एवं Web Feature Service (WFS) आधारित डेटा एकीकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों के डेटा को रियल-टाइम अपडेट करने की व्यवस्था विकसित की गई है। इससे परियोजना नियोजन, अनुमोदन एवं निगरानी की प्रक्रियाएं अधिक सटीक, पारदर्शी और प्रभावी बनी हैं।

इस डिजिटल प्लानिंग मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों में बेहतर समन्वय, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद मिली है। 'साउथ कोस्टल कॉरिडोर' जैसी परियोजनाओं में समय और लागत दोनों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

83,000 हैंडपंपों की जियो-टैगिंग से लेकर 14 नई राशन दुकानों तक, पीएम गतिशक्ति से नागरिक सेवाओं में बड़ा बदलाव

पीएम गतिशक्ति का प्रभाव अब सीधे नागरिक सेवाओं में भी दिखाई दे रहा है। गुजरात जलापूर्ति बोर्ड ने 83,000 हैंडपंप, 5,000 से अधिक सम्प और 3,000 से अधिक एलिवेटेड सर्विस रिज़र्वायर (ESR) की जियो-टैगिंग कर जल जीवन मिशन और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन को डिजिटल बनाया है, जिससे मॉनिटरिंग और सेवा वितरण अधिक प्रभावी हुआ है।

इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 'डायनामिक गैप एनालाइजर टूल' के माध्यम से आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान कर वर्ष 2024-26 के लिए 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और 5 सब-सेंटर स्वीकृत किए हैं। वहीं बनासकांठा जिला प्रशासन ने भी स्पेशयल एनालिसिस टूल्स की मदद से 15 वंचित गाँवों के लिए 14 नई उचित मूल्य दुकानों को मंजूरी दी है। इतनी ही नहीं, शिक्षा विभाग ने भी पीएम पोषण योजना के अंतर्गत केंद्रीकृत रसोईघरों के लिए उपयुक्त भूमि चयन की प्रक्रिया को कई सप्ताह से घटाकर कुछ घंटों में पूरा करना संभव बनाया है।

देश का पहला 'डिजिटल रिज़र्वयर मैनेजमेंट सिस्टम' गुजरात में लागू

पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गुजरात ने मत्स्य क्षेत्र में भी तकनीक आधारित सुशासन की नई मिसाल पेश की है। मत्स्य विभाग द्वारा पीएम गतिशक्ति गुजरात प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश का पहला 'डिजिटल रिज़र्वयर मैनेजमेंट सिस्टम' विकसित किया गया है, जिसके जरिए 1,000 से अधिक जलाशयों का एंड-टू-एंड डिजिटल प्रबंधन संभव हुआ है।

इस अत्याधुनिक प्रणाली से लीज स्वीकृति प्रक्रिया में उल्लेखनीय तेजी आई है, राजस्व प्रबंधन अधिक पारदर्शी बना है और स्थानीय मछुआरों की भागीदारी को भी नई मजबूती मिली है। साथ ही, जलीय संसाधनों के सतत उपयोग और तकनीक आधारित जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देकर गुजरात ने डिजिटल गवर्नेंस का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है।

जंबूसर का 3,900 करोड़ का बल्क ड्रग पार्क बनेगा नया औद्योगिक हब

पीएम गतिशक्ति पहल अब गुजरात की औद्योगिक विकास रणनीति को भी नई गति दे रही है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) द्वारा जंबूसर में विकसित किए जा रहे 3,900 करोड़ के 815 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 'बल्क ड्रग पार्क' की संपूर्ण मास्टर प्लानिंग पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से 15 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र का डिजिटल विश्लेषण कर रोड कनेक्टिविटी, उपयोगिताओं और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़ी आवश्यकताओं की सटीक पहचान की गई है, जिससे परियोजना की योजना प्रक्रिया अधिक तेज़, समन्वित और परिणामोन्मुख बनी है।

राज्य सरकार ने इस परियोजना के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माना जा रहा है कि पीएम गतिशक्ति आधारित यह डेटा-ड्रिवन प्लानिंग मॉडल गुजरात को देश के अग्रणी फार्मास्युटिकल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ निवेश, रोजगार और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।

गुजरात सरकार ने राजनयिक संबंधों का उपयोग कर इबोला प्रभावित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फंसे भुज के प्रोफेसर की स्वदेश वापसी सुनिश्चित की

▸▸ भुज (कच्छ) स्थित श्री आर.आर. लालन कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमीन समा इबोला प्रभावित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फंसे थे और उन्होंने गुजरात सरकार से मांगी थी मदद

▸▸ गुजरात सरकार, एनएसजीएफ और भारतीय राजनयिक मिशनों की त्वरित कार्रवाई के चलते डॉ. अमीन समा को भारत वापस लौटने के लिए आवश्यक कानूनी अनुमति मिली

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, हम दुनिया के किसी भी कोने में मुश्किल हालात में फंसे गुजरातियों और भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ गुजरात राज्य अनिवासी गुजराती फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय और भारतीय राजनयिक मिशनों के समन्वित प्रयासों से, हम एक चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हालात में फंसे नागरिक को समय पर सहायता पहुंचाने में सफल रहे हैं : उप मुख्यमंत्री

गांधीनगर : गुजरात सरकार के त्वरित हस्तक्षेप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के गोमा शहर में लगभग एक महीने से फंसे भुज (कच्छ) के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमीन समा के लिए सुरक्षित तरीके से स्वदेश वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर अमीन इबोला वायरस रोग (ईवीडी) संबंधी चिंताओं के कारण रवांडा और कांगो देश की सीमाओं पर लागू आवागमन के प्रतिबंधों के कारण वहां फंसे हुए थे।

भारतीय नागरिक और भुज के श्री आर.आर. लालन कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉ. अमीन समा 15 मई, 2026 को किगाली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवांडा पहुंचे थे। वहां से वे अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए कानूनी तौर पर डीआरसी के गोमा शहर में दाखिल हुए, जहां से उनका तंजानिया की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम था। हालांकि, केवल दो दिनों के बाद ही इबोला का प्रकोप फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए रवांडा सरकार ने डीआरसी के साथ अपनी सीमा (बॉर्डर) को बंद कर दिया, जिसके कारण वे किगाली वापस नहीं लौट पाए।

अचानक बॉर्डर बंद होने के चलते डॉ. समा की आगे की यात्रा की योजना बाधित हो गई और 31 मई को भारत वापस लौटने की उनकी निर्धारित फ्लाइट भी छूट गई।

डॉ. अमीन समा ने भारत वापस आने के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री के कार्यालय से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। यह मामला श्री हर्ष संघवी के कार्यालय के संज्ञान में आने पर फंसे हुए नागरिक को उचित सहायता-मदद मुहैया कराने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तहत कार्यरत एनआरआई डिविजन के गुजरात राज्य अनिवासी गुजराती फाउंडेशन (एनएसजीएफ) ने तत्काल इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। फाउंडेशन ने तेजी से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ समन्वित प्रयास शुरू किए। 10 जून को नई दिल्ली स्थित अधिकारियों तथा रवांडा और डीआरसी से संबंधित मामलों को संभालने वाले भारतीय दूतावासों को इस बारे में अभ्यावेदन भेजा गया। डॉ. समा के सुरक्षित मार्ग के सभी विकल्प तलाशने के लिए दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया।

इस पूरे समय के दौरान फाउंडेशन के अधिकारी डॉ. समा के साथ लगातार संपर्क में रहे। अधिकारियों ने हालात पर नजर रखते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इतना ही नहीं, फाउंडेशन ने विदेश मंत्रालय और दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहकर यह सुनिश्चित किया कि आवश्यक अनुमतियां व स्वीकृतियां प्राप्त करने में किसी प्रकार का विलंब न हो। इस दौरान डॉ. समा ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने इबोला प्रभावित किसी भी क्षेत्र की यात्रा नहीं की है और वे पूरी तरह से स्वस्थ एवं लक्षणमुक्त हैं। उन्होंने रवांडा, डीआरसी या भारत के अधिकारियों के अनुसार आवश्यक मानी जाने वाली किसी भी चिकित्सा जांच, क्वारंटाइन प्रक्रिया, इबोला टेस्ट, इमिग्रेशन जांच या अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी तैयारी दिखाई। 18 जून को उनकी पुनर्निर्धारित की गई स्वदेश लौटने की फ्लाइट का समय पास आने पर फाउंडेशन ने अपने प्रयास तेज कर दिए और अधिकारियों के साथ दिन में कई बार संपर्क किया। 16 जून को दूतावास के अधिकारियों के साथ हुई आगे की चर्चा में आश्वस्त किया गया कि रवांडा स्थित भारतीय दूतावास मामले को सक्रिय रूप से संभाल रहा है और आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं।

निरंतर प्रयासों के चलते अंततः सकारात्मक सफलता मिली। 17 जून को डॉ. समा को ट्रांजिट और भारत वापस लौटने के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरियां-अनुमतियां मिल गईं, जिससे 18 जून को उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी का रास्ता खुल गया।

मंजूरी मिलने के बाद डॉ. समा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे अभी-अभी यात्रा के लिए अनुमति मिली है। मैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मिले सहयोग और मदद के लिए हृदयपूर्वक आभारी हूं। इस मुश्किल वक्त में आपकी सहायता मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और मैं आपके प्रयासों तथा उदारता को हमेशा कृतज्ञतापूर्वक याद रखूंगा।"

अधिकारियों ने कहा कि इस केस का सफल समाधान विदेश में संकट में फंसे गुजरातियों और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में दुनिया के किसी भी कोने में मुश्किल में फंसे गुजरातियों और भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने की हमारी प्रतिबद्धता है। गुजरात राज्य अनिवासी गुजराती फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय और भारतीय राजनयिक मिशनों के समन्वित प्रयासों से हम एक चुनौतीपूर्व अंतरराष्ट्रीय हालात में फंसे नागरिक को समय पर मदद पहुंचा पाए हैं।"

गुजरात राज्य अनिवासी गुजराती फाउंडेशन ने भी दुनियाभर के गुजरातियों और भारतीय नागरिकों को मार्गदर्शन, समन्वय और संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

वडोदरा में मौत बनकर दौड़ी रफ्तार, लग्जरी बस ट्रक से भिड़ी; पांच यात्रियों की दर्दनाक मौत, 25 से अधिक घायल

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। राजस्थान से गुजरात आ रही एक लग्जरी निजी बस और सड़क किनारे खड़े ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और कई यात्री उसके भीतर बुरी तरह फंस गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरातफरी का माहौल बन गया। बचाव दलों को यात्रियों को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

जानकारी के अनुसार बालाजी ट्रेवल्स की एक लग्जरी बस राजस्थान के बाड़मेर से सूरत की ओर जा रही थी। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जो अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। बुधवार तड़के जब बस वडोदरा शहर के कोटंबी स्टेडियम के पास पहुंची, तभी अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया। देखते ही देखते तेज रफ्तार बस सामने खड़े एक ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आगे बैठे यात्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग जब घटनास्थल की ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि बस का अगला भाग ट्रक में घुस गया था और कई यात्री घायल अवस्था में मदद के लिए पुकार रहे थे। कुछ यात्री सीटों के बीच फंस गए थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर बस के भीतर ही पड़े थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) तथा

वडोदरा अग्निशमन विभाग को भी तत्काल बुलाया गया। राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर शुरू किया गया। बचावकर्मियों ने गैस कटर और अन्य उपकरणों की सहायता से बस के क्षतिग्रस्त हिस्सों को काटकर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

कई घंटे तक चले इस अभियान के दौरान घायलों को एक-एक कर एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल वडोदरा के सरकारी एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन व्यवस्था सक्रिय कर दी और डॉक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कई यात्रियों को सिर, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। इसी कारण प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अस्पताल में घायलों के परिजनों का पहुंचना लगातार जारी है और वहां भावुक दृश्य देखने को मिल रहे हैं।

हादसे के बाद कोटंबी स्टेडियम क्षेत्र और आसपास के मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक सड़क पर ही फंसे रहने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को डायवर्ट किया। बाद में क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका।

प्रशासन ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों और घायलों के परिवारों को सूचना दी जा रही है। कई यात्री राजस्थान और गुजरात के विभिन्न जिलों के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद दोनों राज्यों के प्रशासन के बीच भी समन्वय स्थापित किया गया है ताकि प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

प्रारंभिक जांच में दुर्घटना के पीछे तेज रफ्तार और चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण खो देना संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। यह भी जांच की जा रही है कि ट्रक सड़क किनारे किस परिस्थिति में खड़ा था और क्या वहां पर्याप्त सुरक्षा संकेत लगाए गए थे या नहीं। बस की तकनीकी स्थिति, चालक की कार्य अवधि तथा सड़क की परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के बीच यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी की बस सेवाओं में चालक की थकान, अत्यधिक गति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ऐसे मामलों में नियमित निगरानी और सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

फिलहाल वडोदरा में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पांच लोगों की मौत और दर्जनों यात्रियों के घायल होने से कई परिवार गहरे सदमे में हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ दुर्घटना की जांच में जुटा हुआ है, जबकि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है।

चीकदा तालुका के उमराण में आयोजित जनकल्याण शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम में 'आप' विधायक चैतर वसावा उपस्थित रहे

▸▸ चैतर वसावा की उपस्थिति में उमराण में जनकल्याण शिविर में लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए

▸▸ सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचना आवश्यक है: चैतर वसावा

▸▸ शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता: चैतर वसावा

▸▸ योजनाओं की जानकारी के अभाव में किसान लाभ से वंचित न रहें: चैतर वसावा

▸▸ सरकार, अधिकारी और जनता मिलकर विकास संभव बना सकते हैं: चैतर वसावा

▸▸ कृषि क्षेत्र में सब्सिडी और सहायता योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन देने की आवश्यकता: चैतर वसावा

अहमदाबाद/नर्मदा/गुजरातः नर्मदा जिले के चीकदा तालुका की जनता की विभिन्न लंबित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक विद्यालय उमराण में

"जनकल्याण शिविर" और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विभिन्न निर्वाचित पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर विधायक चैतर वसावा ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुँचे, इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तथा अन्य विकास संबंधी चुनौतियाँ हैं, जिनके समाधान के लिए लगातार कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र में भी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें सब्सिडी, कृषि उपकरण, पशुपालन, सोलर पंपसेट, ट्रैक्टर सहायता, बागवानी खेती तथा अन्य कृषि उपकरणों के लिए सहायता योजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने जोड़ा कि कई बार किसानों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाने के कारण वे इनका लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए अधिकारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार, अधिकारी और जनता मिलकर काम करेंगे तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है।

अमरेली के वडिया गांव में आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार से मिले AAP विधायक गोपाल इटालिया

▸▸ मनसुखभाई ने आत्महत्या से पहले वीडियो में बताया था कि भाजपा नेताओं के उत्पीड़न के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं: गोपाल इटालिया

▸▸ पुलिस FIR में आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भाजपा नेताओं के नाम लिखना नहीं चाहती: गोपाल इटालिया

▸▸ हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलती है लेकिन हिंदू किसान को मरने से सरकार रोक नहीं सकती: गोपाल इटालिया

▸▸ भाजपा के लोग दबंगई कर रहे हैं, उसके खिलाफ मामलतदार, कलेक्टर, DySP सहित सभी लोग सजग बनें और किसानों की मदद करें, इस संबंध में आज प्रस्तुति की: गोपाल इटालिया

अहमदाबाद/अमरेली/गुजरातः अमरेली जिले के वडिया गांव के किसान मनसुखभाई सोजीत्रा ने आत्महत्या कर ली थी और गत दिवस आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया सहित नेताओं ने मृतक मनसुखभाई के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद विधायक गोपाल इटालिया ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए

कहा कि अमरेली जिले के वडिया गांव के किसान मनसुखभाई सोजीत्रा ने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था और वीडियो में उन्होंने कहा था कि भाजपा के कुछ नेताओं के उत्पीड़न के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। इस प्रकार की बात कहकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और आज वे हमारे बीच नहीं हैं। इसके बाद समाज और मनसुखभाई के परिवार के अग्रणी लोग वडिया पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन वडिया पुलिस स्टेशन ने भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि "भाजपा नेता का नाम FIR में नहीं लिखा जाएगा, यदि कहना हो तो किसी छोटे-मोटे नेता का नाम लिख देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा।" आगे विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि हमारे अमरेली जिले के वडिया गांव में एक हिंदू किसान आत्महत्या कर ले और हिंदुत्व के नाम पर चलने वाली पूरी सरकार यदि किसी व्यक्ति को मरने से नहीं रोक सके तो यह बहुत दुखद बात है। मृतक मनसुखभाई के पारिवारिक भाई जीवराजभाई ने भी जमीन के मामले को लेकर आज बहुत दुखी स्वर में कहा कि उन्हें भी रास्ते की समस्या है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ सकती है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है और रास्ते के प्रश्नों को लेकर भाजपा के लोग जो दबंगई कर रहे हैं, उसके खिलाफ मामलतदार, कलेक्टर, DySP सहित सभी लोग सजग बनें और किसानों की मदद करें, इस संबंध में आज जानकारी दी है तथा शीघ्र ही मृतक मनसुखभाई और उनके पारिवारिक भाई जीवराजभाई दोनों के रास्ते के प्रश्न का मामलतदार समाधान निकाले, इस विषय पर भी बात की है।

सूरत नगर निगम को उड़ाने की ईमेल से धमकी, जांच में अफवाह साबित होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक अज्ञात व्यक्ति ने सुबह 11 बजे सूरत नगर निगम के मेयर के ईमेल पते पर एक ईमेल भेजा, जिसमें सूरत नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एसएमसी ने तुरंत इस ईमेल की सूचना लालगेट पुलिस स्टेशन को दी और पुलिस काफिला एसएमसी के सभी कार्यालयों को खाली कराने के लिए रवाना हुआ। सभी कर्मचारियों को एसएमसी परिसर से बाहर भेज दिया गया और पूरे एसएमसी भवन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद, शहर की पुलिस मशीनरी के विभिन्न विभागों जैसे डीसीबी, पीसीबी, एसओजी, डॉग स्क्वाड आदि के अधिकारियों ने एसएमसी में गहन निरीक्षण किया। पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि ईमेल केवल डराने के लिए भेजा गया था। निरीक्षण के दौरान कहीं भी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली और सभी ने राहत की सांस ली।

वडोदरा और जामनगर नगर निगमों को भी इसी तरह के ईमेल प्राप्त हुए, और इन शहरों की पुलिस ने भी मामले की गंभीरता से जांच की। पता चला कि ईमेल केवल डराने-धमकाने के उद्देश्य से भेजे गए थे। वडोदरा और जामनगर में कुछ भी आपत्तिजनक न पाए जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली।